ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टूट गई पीपीपी की एक पीपनी

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआईसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठे कुछ अक्ल के अंधे अफ़सरों ने आईसीयू के नाम पर होने वाले रैफरल खर्च को घटाने के लिये अपने इस अस्पताल में पीपीपी की पीपनी बजानी शुरू करी थी जो 24 अक्तूबर को टूट गयी।

गंभीर मरीज़ों को सघन चिकित्सा (आईसीयू)हेतु प्राइवेट अस्पतालों को रेफ़र किया जाता रहा है। इसके भारी-भरकम बिल को बचाने के लिये ईएसआई कॉर्पोरेशन के अफ़सरों ने बजाये अपने अस्पताल में खुद की आईसीयू बनाने के एक निजी कम्पनी को पीपीपी मोड में इसका ठेका दे दिया। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।

ठेकेदार कम्पनी ने गत माह ईएसआई अधिकारियों से यह कह कर 48 घंटे आईसीयू बंद करने की परमीशन मांगी कि उसे वार्ड को बैक्टिरिया रहित करने के लिये फ्यूमिंग करनी है। परमीशन दे दी गई, परिणामस्वरूप 24 अक्तूबर को ठेकेदार वार्ड पर ताला लगा कर ऐसा गया कि खबर लिखे जाने तक उसका कोई अता-पता नहीं। ऐसे में ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी हर रोज़ सुबह काम के लिये आते हैं और दिहाड़ी बर्बाद करके लौट जाते हैं।

उधर अस्पताल के लिये भी यकायक समस्या पैदा हो गई। कुछ मरीज़ों को तो अस्पताल अपने यहां अस्थाई से आईसीयू वार्ड में रख रहा है। बाकी गंभीर मरीज़ों को पुनः निजी अस्पतालों को रैफ़र कर रहा है। संदर्भवश पाठक जान लें कि पिछले कई अंकों में 'मज़दूर मोचा' ने ईएसआई के महानिदेशक के वे बयान प्रकाशित किये थे जिनमें रैफरल बिलों को घटाने के लिये अपने अस्पतालों में पर्याप्त आवश्यक सुविधायें बढाने को कहा था।

करीब दो वर्ष तक ठेके पर चले इस आइसीयू वार्ड में न तो आवश्यकतानुसार पर्याप्त कर्मचारी थे और न ही डॉक्टर। इसके बावजूद ठेकेदार को 4500 रुपये प्रति मरीज़ प्रति दिन के हिसाब से अदा किया जाता रहा। वार्ड के तीसों बेड हमेशा फुल रहते थे। इसके बावजूद ठेकेदार घाटा महसूस कर रहा था। लिहाज़ा उसने वार्ड में बेड की संख्या 30 से घटाकर 15 कर दी थी और अब इस तरह से बिना बताये धोखा देकर वार्ड को ताला लगाकर भाग गया। ईएसआई मुख्यालय में बैठे नालायक एवं जनविरोधी जिन अफ़सरों ने ठेकेदार को यहां बैठाया था, वे अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्हें मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़ करने में कतई कोई शर्म लिहाज नहीं है। अपने अव्याशियों पर तो वे मज़दूर के करोड़ों रुपये बर्बाद कर सकते हैं लेकिन मज़दूरों को सुविधायें देने के समय उनको कंजूसी करने की सूझती है। 'मज़दूर मोर्चा' ने उस वक्त भी इस पीपीपी मोड का विरोध किया था। मुख्यालय में बैठे अधिकारियों का वश चले तो वे सारे अस्पताल को ही पीपीपी मोड में सौंप दें। अपनी इसी नीयत का प्रदर्शन करते हुये उन्होंने डायलेसिस का काम भी पीपीपी मोड में दे रखा है। इसके चलते कई मरीज़ों को भारी परेशानियां हो रही हैं। यहां चलने वाली लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई एक मृत्यु का विवरण भी 'मज़दूर मोर्चा' में गत वर्ष प्रकाशित किया गया था।

पीपीपी के शौकीन इन अफ़सरों का वश चलता तो एमआरआई व सीटी स्कैन भी पीपीपी मोड में दे दिया जाता। परंतु कुछ कानूनी एवं व्यवहारिक मजबूरियों के चलते उनका यह इरादा सफ़ल नहीं हो पाया। इसके चलते अब इस अस्पताल में उक्त दोनों उपकरण लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

तिगांव अस्पताल की हरामखोरी के चलते बीके अस्पताल के दरवाजे पर डिलिवरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक दो नवम्बर को सुदेश कुमार अपनी पत्नी रोशनी को डिलिवरी हेतु बीके अस्पताल लेकर आया था कि इमरजेंसी गेट पर ही डिलिवरी हो गयी। इससे पहले पति-पत्नी तिगांव के उस अस्पताल में गये थे जिसके नये भवन निर्माण का उद्घाटन कुछ माह पूर्व नारियल फ़ोड़ केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने किया था। उस वक्त **'मज़दूर मोर्चा'** ने लिखा था कि ड्रामेबाज़ों की यह सरकार हर तरह के ड्रामे तो करती है परन्तु वह काम कतई नहीं करती जिसकी जरूरत आम जनता को है।

विदित है कि तिगांव के कम्युनिटी हैल्थ सेंटर (सीएचसी) में 6 डॉक्टर, 7 नर्स व 8 अन्य स्टाफ़ के स्वीकृत पद हैं। लेकिन मौजूद हैं 3 डॉक्टर, 4 नर्स (वे भी ठेके पर) व 3 अन्य स्टाफ़। प्रशासनिक हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते यह स्टाफ़ भी या तो ड्यूटी से नदारद रहता या फ़िर आने वाले मरीज़ों को बीके या अन्य अस्पतालों की ओर धकेल देता है।

मौजूदा मामले में रोशनी की डिलिवरी बहुत ही सामान्य यानी कि इतनी सामान्य कि खुद ही हो गयी और जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। ऐसे केस में तिगांव के अस्पताल को क्या मौत पड़ रही थी जो उसने डिलिवरी कराने की अपेक्षा उसे बीके अस्पताल की ओर धकेल दिया। हरामखोरी का यह नमूना न तो पहला है न आखिरी। ऐसे हर कारनामे की जांच का एक नाटक रचा जाता है, ले-दे कर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है और ऐसे अन्य मामले का इन्तज़ार किया जाता है।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100,500 रुपये 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

'खट्टर की लफ़्फाज नौटंकी के पूरे हुए चार साल'

मज़दूर मोर्चा के 23 अक्तूबर-3 नवम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर लगाये गये घूसखोरी के आरोपों से देश में बवंडर मच गया है। इसके लिये दोषी स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। मोदी-शाह दोनों की प्रवृति केन्द्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने की है। दोनों अपनी नीति व विचारों के विरुद्ध विपक्षी अथवा अपनी ही पार्टी के विचार को सुनने को तैयार नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां गुजरात मॉडल नाम से केन्द्रीकृत शासन स्थापित कर रखा था। वहीं सीबीआई के वर्तमान स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना मोदीजी के खास चहेते बन गये थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने गुजरात कैडर के अपने वफ़ादार अधिकारियों को केन्द्र में पीएमओ तथा अन्य संवैधानिक विभागों में तैनात कर दिया। दो साल पहले मोदी जी ही अस्थाना को अतिरिक्त निदेशक के रूप में सीबीआई में लाये थे और और जब मोदीजी अस्थाना को अतिरिक्त निदेशक से स्पेशल डायरेक्टर बनाना चाहते थे तब डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर (सीवीसी) को पत्र लिखकर सूचित किया कि अस्थाना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आये हैं और उनकी जांच चल रही है। लेकिन ना तो सीवीसी ने और ना मोदीजी ने इस पत्र पर ध्यान दिया और अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बना दिया।

सीनियर वकील प्रशांत भूषण, भाजपा नेता यशवंत सिन्हा तथा पूर्व भाजपा केन्द्रीय मंत्री अरूण शौरी ने आलोक वर्मा से मुलाकात कर राफ़ेल डील में घोटाले के अहम दस्तावेज सौंपे, इस पर मोदीजी आलोक वर्मा से नाराज हो गये। इससे पूर्व आलोक वर्मा ने अस्थाना के भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी थी। इस पर नाराज होकर मोदी सरकार ने अपने वफ़ादार सीवीसी के ज़रिए 24 अक्तूबर को रातो-रात आलोक वर्मा तथा अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया और आलोक वर्मा की जगह नगेश्वर राव को डायरेक्टर नियुक्त कर दिया, परंतु राव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुये हैं। नये डायरेक्टर ने पर संभालते ही 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसमे अस्थाना के विरुद्ध जांच कर रहे अधिकारी भी थे। जांच अधिकारी डीएसपी ए.के.बस्सी ने दावा किया है कि उनके पास अस्थाना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के ठोस सबूत हैं।

'सीबीआई बनाम सीबीआई नहीं अमित शाह बनाम अहमद पटेल' में बेबाक विवेचन किया गया है कि सभी सत्तारूढ दल अपने राजनीतिक हित साधने के लिये सीबीआई जैसी संस्थाओं में अपने चहेतों की नियुक्ति करती रही है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी उनसे पूर्ण समर्पण चाहते हैं और धैंसपट्टी से काम करवाते हैं। यद्यपि आलोक वर्मा ने मोदी-शाह से निभाया जैसे मायावती और मुलायम सिंह यादव पर कांग्रेस के जमाने से लटकती तलवार का हौव्वा बनाए रखा, व्यापमं घोटाले को ठंडे बस्ते में डाले रखा आदि, परंतु मोदी-शाह समर्थित अस्थाना की चालबाजियों के आगे घुटने नहीं टेके और अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता दिखाई जो मोदी सरकार को सहन नहीं हुआ। आलोक वर्मा के निवास के बाहर घूम रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के चार अधिकारियों को जासूसी के आरोप में वर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की। हैरानी की बात रही कि आईबी की शिकायत पर वर्मा के सुरक्षाकर्मियों का तो तबादला कर दिया लेकिन आईबी के अधिकारियों के विरुद्ध इस जासूसी विवाद में कोई कार्यवाई नहीं की गई।

'मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे पर कालख पुतीं', में मोदी व अस्थाना के बीच गहरे रिश्तों का भंडाफ़ोड़ किया गया है। मोदीजी का कहना कि 'ना खाउंगा और न खाने दूंगा' इस सीबीआई प्रकरण से खोखला साबित हो रहा है। इस विवाद से मोदी सरकार तथा स्वयं मोदीजी की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है तथा 'ईमानदार' व 'भ्रष्टाचार मुक्त' शासन का आवरण उतर गया है।

'खट्टर के लफ़्फाज नौटंकी के पूरे हुए चार साल' में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपने शासन के चार साल पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपाते हुये तमाम प्रचार साधनों द्वारा जनता के सामने गिनाई जा रही तथाकथित उपलब्धियों जैसे लड़कियों के लिये 32 नये कॉलेज खोलने की थोथी घोषणा, स्कूलों व कॉलेजों की दुर्दशा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के झूठे दावे तथा जीरो भ्रष्टाचार के खोखले दावे आदि का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।'' 'ईमानदार' खट्टर की देखी 'ईमानदारी' अपहरण करने वाले इस्पेक्टर को गैलेंटरी मैडल'' में एक बिल्डर का अपहरण करके वसूली करने वाले इन्सपेक्टर वरुण को गैलेंटरी मैडल के लिये भारत सरकार को रिकमेंड करने पर खट्टर की प्रशासन व्यवस्था की पोल खोली गई है।

मोदी सरकार ने मीडिया पर पूरी तरह से नकेल कस रखी है और मीडिया सरकार के कदमों में लोटपोट करने को तैयार बैठा है जो हर विवाद में जनता के सामने सरकारी पक्ष को ही परोस रहा है। टाइम्स नाऊ चैनल द्वारा सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाने से प्रभावित छवि पर आयोजित डिबेट का विषय अचानक बदलने पर योगेन्द्र यादव द्वारा डिबेट का बहिष्कार करने का 'योगेन्द्र यादव बनाम टाइम्स नाऊ...जब योगेन्द्र यादव ने विवादास्पद टाइम्स नाऊ को लाइव ही धो डाला' में विवेचन किया गया है, जिससे टाइम्स नाऊ चैनल की असहन-शीलता जनता के सामने आ गई है। 'पत्रकार हमेशा सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है-गणेश शेकर विद्यार्थी' में वर्णित पत्रकारिता का महत्व आज के संदर्भ में बिल्कुल प्रासंगिक है।

देश की तमाम स्वायत संस्थाओं के प्रशासन में मोदी सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें उनकी प्रकृति के अनुरूप स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं की आजादी का मुद्दा गरमाता रहा है। लेकिन अब सीबीआई के बाद रिजर्व बैंक इंडिया (आरबीआई) से भी यह आवाज उठी है। 'केन्द्र के खिलाफ़ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने भी मुंह खोला....आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने केन्द्र सरकार की घंटी बजाई सीबीआई के बाद अब आरबीआई में आजादी छिनने से चिंता बढी' में डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की मांग कि उन्हें आज़ादी दो और स्वतंत्रता से काम करने दो से आरबीआई के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। आचार्य ने कहा है कि आरबीआई की स्वायत्तता कमजोर पड़ी तो उसके खतरनाक परिणाम सामने आयेंगे। इससे कैपिटल मार्केट्स में संकट खड़ा हो सकता है,जहां से सरकार भी कर्ज लेती है।

गौरतलब है कि सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के मद्देनज़र आरबीआई बोर्ड में अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति की है, जिन्हें कोई व्यापारिक (वाणिज्य) अनुभव नहीं है और बोर्ड में स्थाई व अस्थाई सदस्यों के बीच दो गुट बन गये हैं। एक सरकार को तात्कालिक लाभ पहुंचाना चाहता है तो दूसरा अर्थव्यवस्था को दूरगामी नजरिये से देखता है और उसे नियमों के अनुसार चलाना चाहता है।'आजादी' मांग रहे आरबीआई से वित्तमंत्री अरूण जेटली काफ़ी नाराज हुये और उन्होंने 2008 से 2014 के बीच बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज के बहाने आरबीआई की तीखी आलोचना की।

'मनमोहन सिंह का यूपीए का कार्यकाल आज के मोदी राज की तुलना में बेहतर नज़र आने लगा है' में पर्दाफ़ाश किया गया है कि मोदीराज में यूपीए काल से कहीं ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। मोदी सरकार सीबीआई, सीवीसी, आरबीआई, एन्फ़ोर्समैंट डायरेक्टरेट (ईडी) आदि में पूरी दखलंदाज़ी कर रही है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को अप्रासंगिक बनाने में तुली हुई है। सीआईसी द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मांगी गई सूचनायें मुहैया नहीं कराई जा रही और सीआई सी में खाली पड़े 4 आयुक्तों के पद भी नहीं भरे जा रहे।

यूपी पुलिस द्वारा क्रिमिनल का एनकाऊंटर करते समय पुलिस की बंदूक से गोली न चलने पर मुंह से ठांए-ठांए करने पर 'यूपी पुलिस ने बंदूक नहीं चली तो मुंह से ठांए-ठांए किया बम मिसाइल वगैरह की आवाज भी निकाल लेते हो क्या,' कांग्रेस व भाजपा दोनों द्वारा भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ने पर 'जनता पता नहीं कब समझेगी' तथा आगामी विधानसभा व लोकसभा के चुनावों के मद्देनज़र मोदी द्वारा राम मंदिर का राजनीतिकरण करने पर 'तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें राम मंदिर दूंगा!!!' कार्टूनों द्वारा उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।